



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

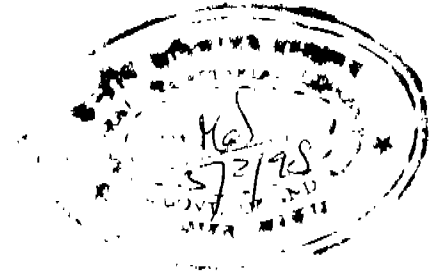
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section—3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 653]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 1997/अग्रहायण 7, 1919

No. 653]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 1997/AGRAHAYANA 7, 1919

शहरी कार्य और नियोजन मंत्रालय

(सम्पदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1997

का. आ. 803 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा सरकारी स्थानों के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों, किसी राज्य सरकारी से संबंधित या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर लिए गये राष्ट्रीय दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र या किसी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सरकारी स्थान की बाबत उस राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

[फा. सं. 21012/3/96-पोल-1]

आर. डी. सहाय, उप सम्पदा निदेशक

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT

(Directorate of Estates)

NOTIFICATION

New Delhi, 21st December, 1997

S.O. 803 (E).—In exercise of powers conferred by section 17 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby directs that the powers exercisable by the Central Government under section 3 of the said Act for appointment of estate officers for the purposes of public premises shall be exercisable also by a State Government or an officer of the State Government as authorised by that State Government for the public premises belonging to or taken on lease by, or on behalf of that State Government and situated in the National Capital Territory of Delhi or in any other Union territory.

[File No. 21012/3/96-Pol. I]

R. D. SAHAY, Deputy Director of Estates

3027 GI/97

